



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

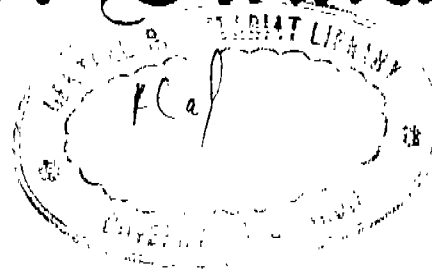
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 132 ]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 25, 2001/ज्येष्ठ 4, 1923

No. 132]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 25, 2001/JYAISTHA 4, 1923

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 मई, 2001

सं. टीएएमपी/25/2001-एनएमपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्वारा संलग्न आदेशानुसार वर्ष 1999-2000 के दौरान न्यू मेंगलौर पत्तन न्यास से कुद्रेमुख लौह अयस्क कम्पनी लिमिटेड (केआईओसीएल) द्वारा निर्यात किए गए लौह अयस्क पर घाटशुल्क प्रभार निर्धारित करता है।

अनुसूची

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला सं. टीएएमपी/25/2001-एनएमपीटी

न्यू मेंगलौर पत्तन न्यास (एनएमपीटी)

आवेदक

आदेश

(मई, 2001 के 16वें दिन पारित किया गया)

यह मामला वर्ष 1999-2000 के दौरान एनएमपीटी के माध्यम से निर्यात किए गए लौह अयस्क की घाटशुल्क दर का परिकलन संबंधित वर्ष के दौरान होने वाले वास्तविक खर्च के अनुसार किया गया है। केआईओसीएल के अयस्क के संबंध में घाटशुल्क दरें निर्धारित

करने की कार्यपद्धति, 27 मई 1992 को सचिव (एमओएसटी) और सचिव (स्टील) के बीच हुई अंतर-सचिवीय बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार है। उस बैठक में यह निर्णय किया गया था कि केआईओसीएल की घाटशुल्क दर निम्नलिखित विभिन्न घटकों के संबंध में हुए वास्तविक खर्च के आधार पर प्रतिवर्ष निर्धारित की जाएगी :-

- (i) यातायात विभाग के प्रचालन खर्च का हिस्सा।
- (ii) वास्तविक निकर्षण खर्च का 75%।
- (iii) मूल्यह्रास।
- (iv) प्रबंधन और प्रशासनिक उपरिव्ययों का हिस्सा।
- (v) पूंजी पर ब्याज।
- (vi) पूंजी पर प्रतिलाम।

3. एनएमपीटी ने बताया है कि वर्ष 1999-2000 की घाटशुल्क दर द्विपक्षीय करारों के अनुसार एमआरपीएल, केआईओसीएल और एनएमपीटी के बीच खर्च के नियत घटकों के विभाजन पर विचार करते हुए तय की गई है। वास्तविक व्यय के आधार पर वर्ष 1999-2000 की अंतिम दर 30.76 रुपए प्रति मीट्रिक टन तय की गई है।

4. एनएमपीटी ने यह भी सूचित किया कि घाटशुल्क के परिकलन की यह पद्धति केआईओसीएल द्वारा परीक्षित की गई है, जिसने अभिलेखों के सत्यापन के पश्चात लिखित में दर की पुष्टि की है।

5. इस मामले की कार्यवाही के दौरान एकत्र की गई समग्र सूचना के संदर्भ में निम्नलिखित स्थिति प्रकट होती है :-

- (i) वर्ष 1999-2000 के लिए एनएमपीटी से केआईओसीएल द्वारा निर्यात किए गए लौह अयस्क पर घाटशुल्क 30.76 रुपए प्रति मीट्रिक टन की दर पर निर्धारित करने का एनएमपीटी का प्रस्ताव दरों के पूर्वप्रभाव से अनुमोदन का मामला है। स्वीकार्य दर पर पहुंचने के लिए पत्तन और प्रयोक्ता के बीच राय में कोई भिन्नता नहीं है। इस प्राधिकरण ने इससे पूर्व वर्ष 1995-96, 1996-97, 1997-98 और 1998-1999 के लिए एनएमपीटी से केआईओसीएल द्वारा निर्यात किए गए लौह अयस्क की घाटशुल्क दर समान आधार पर अनुमोदित की थी। वर्ष 1998-99 के लिए कुद्रेमुख लौह अयस्क पर घाटशुल्क की अनुमोदित दर 32.49 रुपए प्रति मीट्रिक टन थी।
- (ii) इस मामले में घाटशुल्क के परिकलन के लिए अपनाई गई पद्धति इस प्राधिकरण द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण से थोड़ी भिन्न है। उदाहरणार्थ, निकर्षण अनुकरण पर खर्च, जोकि पोत-संबद्ध खर्च है, पर इस कार्गो-संबद्ध प्रभार का परिकलन के लिए विचार किया गया है। पूंजी निवेश पर प्रतिलाम पर भी अलग ढंग से विचार किया गया है।
- (iii) पत्तन और पत्तन सुविधा के प्रयोक्ता के बीच हस्ताक्षर किया गया समझौता ज्ञापन (एमओयू) ऐसी सेवाओं के लिए प्रशुल्क निर्धारित करने हेतु इस प्राधिकरण को आबद्ध नहीं कर सकता। वर्तमान मामले में यह निश्चित है कि एनएमपीटी द्वारा अपनाई गई पद्धति केआईओसीएल से इतर प्रयोक्ताओं पर अनायश्यक बोझ का कारण नहीं है। एनएमपीटी ने अब अपनी दरों के मान के सामान्य संशोधन के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है और इस संदर्भ में विभिन्न गतिविधियों की वित्तीय/लागत स्थिति की पड़ताल की जा रही है। यदि जाँच से यह प्रमाण चलता है कि केआईओसीएल गतिविधि की सभी संगत लागतों का निर्धारण ठीक प्रकार से नहीं किया गया है तो यह प्राधिकरण केआईओसीएल कार्गो पर घाटशुल्क निर्धारित करने के लिए भविष्यलक्षी रूप से भिन्न पद्धति निर्धारित कर सकता है। ऐसा होने तक, पिछले 10 वर्षों से प्रचलित वर्तमान पद्धति को अब आगे जारी रखने के लिए अनुमति दी जाती है।

6. परिणामस्वरूप, उपर्युक्त तर्कों और विचार-विमर्श के आधार पर यह प्राधिकरण वर्ष 1999-2000 के दौरान न्यू मंगलौर पत्तन से 30.76 रुपए प्रति मीट्रिक टन की दर पर केआईओसीएल द्वारा निर्यात किए गए लौह अयस्क के लिए घाटशुल्क दर निर्धारित करने के लिए एनएमपीटी के प्रस्ताव का अनुमोदन करता है।

7. स्पष्ट रूप से यह पूर्व-प्रभाव से प्रशुल्क निर्धारण का मामला है। परंतु, विधि मंत्रालय ने प्रमाणित किया है कि इस प्राधिकरण को पूर्व-प्रभाव से प्रशुल्क निर्धारित करने का अधिकार है और इस मामले में, जब तक केवल एक प्रयोक्ता संबद्ध है और वह भी प्रस्ताव से सहमत है तो पूर्व-प्रभाव के आदेश से कोई विशेष कठिनाई नहीं होगी।

एस. सत्यम, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/IV/143/असा./2001]

## TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 25th May, 2001

**No. TAMP/25/2001-NMPT.**—In exercise of the powers conferred by Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby fixes the wharfage charges on iron ore exported by the Kudremukh Iron Ore Company Limited (KIOCL) from the New Mangalore Port during the year 1999-2000, as in the Order appended hereto.

### SCHEDULE

#### TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

Case No. TAMP/25/2001-NMPT

The New Mangalore Port Trust (NMPT)

...

Applicant

### ORDER

(Passed on this 16th day of May, 2001)

This case relates to a proposal received from the New Mangalore Port Trust (NMPT) for fixation of final wharfage for the Kudremukh Iron Ore Company's (KIOCL) ore exported through the NMPT for the year 1999-2000.

2. The NMPT has stated that the wharfage rate for the iron ore exported by the KIOCL through the NMPT is calculated with reference to actual expenditure incurred during the year concerned. The methodology of fixation of wharfage rates in respect of the KIOCL ore is in accordance with the decision taken in the Inter-Secretarial meeting between the Secretary (MOST) and the Secretary (Steel) held on 27 May 92. It was decided in that meeting that the wharfage rate for KIOCL should be fixed annually based on the actual expenditure towards the various components as detailed below:

- (i). Share of operating expenditure of Traffic Department.
- (ii). 75% of the actual dredging expenditure.
- (iii). Depreciation.
- (iv). Share of Management and Administration overheads.
- (v). Interest on Capital.
- (vi). Return on Capital.

3. The NMPT has stated that the wharfage rate for 1999-2000 has been worked out taking into consideration the sharing of certain elements of expenditure between MRPL, KIOCL and NMPT as per the bilateral agreements. The final rate for the year 1999-2000 has been worked out based on the actuals, and has been fixed at Rs.30.76 PMT.

4. The NMPT has also intimated that the method of calculation of wharfage has been checked by the KIOCL who, after verification of records, have confirmed the rate in writing.

5. With reference to the totality of information collected during the processing of this case, the following position emerges:

- (i). The proposal of the NMPT to fix the wharfage on iron ore exported by the KIOCL through the NMPT for the year 1999-2000 @ 30.76 PMT is a case of retrospective approval of rates. There is no difference of opinion between the Port and the user in arriving at an agreed rate. This Authority had earlier approved the wharfage rate in respect of iron ore exported by the KIOCL through the NMPT for the years 1995-96, 1996-97, 1997-98 and 1998-99 on the same analogy. The approved rate of wharfage on Kudermukh iron ore was Rs.32.49 PMT for the year 1998 - 99.
- (ii). The method adopted for computation of wharfage in this case is slightly different from the approach followed by this Authority. For instance, expenditure on maintenance dredging, which is a vessel related expenditure, is considered for arriving at this cargo related charges. The return on investment is also considered in a different manner.
- (iii). An MOU signed between a Port and the user of the port facility can not bind this Authority in fixing tariff for such services. In the instant case, it is to be ensured that the method adopted by the NMPT does not cause undue burden on users other than the KIOCL. The NMPT has now come up with a proposal for a general revision of its Scale of Rates; and, in this context, the financial/cost position of various activities is being examined. If the scrutiny reveals that allocation of all relevant costs to the KIOCL activity is not made properly, this Authority may prescribe a different method for fixing wharfage on KIOCL cargo prospectively. Till that happens, the existing method which has been in vogue for nearly 10 years now is allowed to continue.

6. In the result, and for the reasons given above, and based on a collective application of mind, this Authority approves the proposal of the NMPT for fixation of wharfage rate for iron ore exported by the KIOCL during the year 1999-2000 from New Mangalore Port @ Rs.30.76 PMT.

7. This is obviously a case of retrospective prescription of tariff. But, the Ministry of Law has certified that this Authority has the power to prescribe tariffs with retrospective effect. And, in this case, since there is only one user concerned, who has also concurred with the proposal, no particular difficulty is likely to be caused by the retroactive Order.

S. SATHYAM, Chairman

[Advt./III/IV/143/Exty./2001]